तथा उसके द्वारा की गई भविष्यवाणियों के गलत साबित होने की जांच तथा मूल्यांकन करने का विचार रखती हैं,

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा, और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी हां, सरकार ने समपादकीय देखा है।

(ख) से (घ) मानसून मौसम का पूर्वानुमान करने के लिए वर्तमान मॉडल 1988 में क्रियाशील किया गया था और तब से मानसून पूर्वानुमान संतोषजनक सिद्ध हुआ है । 1994 में मॉडल ने एक सामान्य मानसून का सही अंदाजा लगाया था, लेकिन वास्तविक की अपेक्ष्ज्ञज्ञ कम कुल वर्षा की भविष्यवाणी की थी । पूर्वानुमान तकनीकों में सुधार की सतत समीक्षा की जाती है ।

Non-Convcntinal Power Production

466. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government arc considering to promote Small Power Plants under reliable renewable energy and technologies utilising bio-mass, bio-gas solar thermal etc., at the village level;

(b) whether Government arc considering setting up of a separate Corporation for promoting Non-Conventional Power production at the village level; and

(c) if not, whether Government arc considering to promote genrcating of non-conventional energy in the Rural Sector in association with Rural Electrification Corporation'?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) The Government promoting use of solar photovoltaics, small hydro and biomas gasificr technologies for village electrifications in a decentralised manner. These technologies arc proven and also cost economic under site conditions.

(b) No, Sir.

(c) Rural Electrification Corporation is already involved in electrification of remote village with locally available renewable energy resources.

"कापार्ट" द्वारा स्वंयसेवी एजेंसियों को काली सूची में डाला जाना

467. **श्री रामदेव भंडारी :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लोक अभियान तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी समुन्नति परिषद् (कापार्ट) द्वारा राज्य-चार कितने स्वंयसेवी संस्थाओं को काली सूची में डाला गया है,

(ख) इन संस्थाओं को काली सूची में डालने का आधार तथा कारण क्या हैं तथा इस संबंध में जांच करने वाली एजेंसी का नाम क्या है,

(ग) काली सूची में दर्ज इन संस्थाओं को "कापार्ट" द्वारा कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई है और उसमें से कितनी धनराशि के दुरूपयोग होने का अनुमान है,

(घ) धनराशि के दुरूपयोग के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है,

(ड) उन संस्थाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनके संबंध में धनराशि के दुरूपयोग की "कापार्ट" द्वारा जांच की जा रही है, और

(च) क्या "कापार्ट" काली सूची में दर्ज संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही करेगा?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) कापार्ट द्वारा काली सूची में डाले गए स्वंयसेवी संगठनों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्र है । (नीचे देखिए)

(ख) इन स्वंयसेवी सगंठनों को कापार्ट द्वारा मुख्य से निधियों के दुरूपयोग । झूठी सूचनाएं, फर्जी दस्तावेजों आदि के आधार पर काली सूची में डाला गया है । मुख्य एजेंसियों में ऐसे मामलों की जांच करने वाले मंजूर की गई परियोजनओं के कार्यान्वयन की निगरानी के संबंध में कापार्ट द्वारा प्रतिनियुक्त परियोजना मूल्यांकनर्त्ता द्वारा की जाती है ।

(ग) से (ड) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रखा जाएगा ।

(च) जी हां ।

विवरण

राज्य		31.7.1995 **तक कापार्ट द्वारा काली सूची में डाली गई स्वैच्छिक एजेंसियों की संख्या (अंनितम)**
1.	असम	4
2.	आन्ध्र प्रदेश	72
3.	बिहार	71
4.	दिल्ली	17
5.	गुजरात	13
6.	हरियाणा	6
7.	हिमाचल प्रदेश	1
8.	केरल	4
9.	कर्नाटक	16
10.	मध्य प्रदेश	14
11.	महाराष्ट्र	14
12.	मणिपुर	2
13.	उड़ीसा	7
14.	राजस्थान	27
15.	तमिलनाडु	7
16.	उत्तर प्रदेश	74
17.	पं. बंगाल	8
	कुल	359

National Programme for Control of Blindness

468. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) what are the activities undertaken with the assistance of World Health Organisation (WHO) under the National Programme for Control of Blindness;

(b) the States where the assisted project has been taken up; and

(c) whether any monitoring cell has been formed for the avaluation purposes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. SILVERA): (a) World Health Organisation (WHO) funds are used for supply of opthalmic equipments, training of manpower and strengthening of Management Information System (MIS) at the Central level.

(b) These activities are not specified to any particular State.

(c) Yes, Sir.

Life-saving Devices

469. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) Whether Government's attention has been drawn to the news item captioned "Defence technology being used to make life-saving devices" as reported in the Economic Times dated 3rd July, 1995;

(b) whether scientists in the country are using military technology to make life-saving devices, like cardiac pacemakers;

(c) if so, whether Government would use the cardiac pace-makers being developed by scientists; and

(d) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI MALLIKARJUN): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) Defence Research & Development Organisation have successfully developed an external pacemaker for intensive care application. This development work has been sponsored by Society for Bio-Medical Technology (SBMT). The external pacemaker is under clinical trials at Nizam Institute of Medical Sciences, Hyderabad. The implantable version of the pacemaker is under advanced stages of development. After acceptance in clinical trials and productionisation, the cardiac pacemaker would be available for use to general public and hospitals, both in Government and private sectors. The SBMT has already nominated an industry unit in private sector as production agency.